



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1945 (श10)
(सं0 पटना 498) पटना, मंगलवार, 27 जून 2023

सं० 2प/वि०-17-28/2023/7076/पं0रा0
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 26 जून 2023

विषय:-

नवादा जिला अन्तर्गत पंचायत समिति मेसकौर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आंशिक भाग को नगर परिषद हिसुआ में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य के पद पर बने रहने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-841, दिनांक 08.04.2023 द्वारा विभाग को सूचना दी गई है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-1877 दिनांक 14.07.2022 से पंचायत समिति मेसकौर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-7 के आंशिक भाग को नगर परिषद् हिसुआ में सम्मिलित किया गया है। उक्त पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र से श्री संतोष कुमार, पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं एवं तत्पश्चात् वे उक्त पंचायत समिति के प्रमुख के रूप में भी निर्वाचित किये गये हैं। श्री संतोष कुमार जिस क्षेत्र के मतदाता हैं, उस क्षेत्र को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिये जाने के फलस्वरूप वे अब पंचायत के मतदाता नहीं रह गये हैं, ऐसी स्थिति में उनके प्रमुख पद पर बने रहने के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

2. पंचायत आम चुनाव, 2021 में पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लगभग 6 महीने के पश्चात् संबंधित सदस्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आंशिक रूप से शहरी निकाय में सम्मिलित कर लिया गया है,

यानी जब उनका चुनाव हुआ था, तब उनका नाम पंचायत समिति के वोटर लिस्ट में सम्मिलित था तथा वे उक्त पंचायत समिति क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित किये गये थे। जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्र के अनुसार उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का आंशिक भाग नगर निकाय में सम्मिलित किया गया है, यानी उसका कुछ भाग आज भी पंचायत क्षेत्र में बना हुआ है।

3. मुंगेर जिले से संबंधित एक मामले में निर्वाचित हो जाने के पश्चात् मुखिया जिस वार्ड के निवासी थे, वह वार्ड शहरी निकाय में चले जाने के कारण मुखिया के बने रहने या नहीं बने रहने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया था। विधि विभाग का मतव्य था कि अधिनियम में ऐसी स्थिति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं रहने के कारण सरकार अधिनियम की धारा 172 के अधीन (कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति) समुचित निर्णय ले सकती है। सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक-2556 दिनांक 01.03.2023 से निर्णय लिया गया था कि निर्वाचित मुखिया सामान्यतः अपनी पूरी कार्यावधि तक मुखिया के रूप में बने रहेंगे, किन्तु कार्यावधि पूरी हो जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के आलोक में वे अगले किसी पंचायत क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं होंगे। संबंधित पत्र की प्रतिलिपि सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

4. उपर्युक्त आलोक में अधिनियम की धारा-172 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि पंचायत आम चुनाव, 2021 में निर्वाचित किसी पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र आंशिक रूप से शहरी निकाय में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसमें उक्त सदस्य का निवास क्षेत्र भी सम्मिलित है, तो उस क्षेत्र से निर्वाचित यथास्थिति पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद् सदस्य अपने पद पर अपने पूरे कार्यकाल तक बने रहेंगे बशर्ते कि इस बीच वह खुद अपने पद का परित्याग न कर दें या उन्हें बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन विहित प्राधिकार द्वारा पद से हटा नहीं दिया जाय। विहित कार्यावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 135 के अध्याधीन अगले किसी पंचायत आम चुनाव में उन्हें अभ्यर्थी बनने का अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसा पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद् सदस्य यथास्थिति पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख या जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किये गये हैं तो वे ऐसे पद पर तब तक बने रह सकेंगे जब तक अविश्वास प्रस्ताव या लोक प्रहरी की अनुशंसा के आलोक में उन्हें सरकार द्वारा पद से हटा नहीं दिया जाय या वे स्वतः त्यागपत्र दे दें या उनकी मृत्यु हो जाय। अगर संबंधित पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र उनके निवास क्षेत्र सहित पूर्णरूपेण शहरी निकाय में सम्मिलित कर लिया गया है, तो यथास्थिति पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद् सदस्य के रूप में उनके बने रहने का आधार (Locus standi) समाप्त माना जायेगा एवं ऐसी स्थिति में न तो वे पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद् सदस्य रह जायेंगे, न ही पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख अथवा जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष।

5. कृपया सरकार के उक्त निर्णय से सभी संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से अविलम्ब अवगत कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 498-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>